



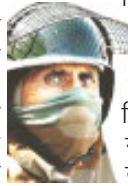
टकराव की नौबत आने की आशंका

हो सकता है बीएसएफ की किसी कार्रवाई से कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो जाए। राज्य सरकारों के असंतोष या उनकी असहमति का सार्वजनिक रूप से जाहिर होना ऐसे संभावित टकराव की जमीन को मजबूत करता है।

आरती सिंह।।

केंद्र सरकार ने अपने एक हालिया फैसले के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा से सटे राज्यों— असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब— में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला हाल के दिनों में सीमा पार गतिविधियों में हुए अप्रत्याशित इजाफे और ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से पैदा हुए विशेष खतरों के मद्देनजर किया गया है। मगर कुछ राज्य सरकारें इसे अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक दखल के रूप में ले रही हैं। पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकारों ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

निश्चित रूप से यह विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर हमारी सरकारें इस तरह एक-दूसरे से सार्वजनिक तौर पर उलझती दिखें तो उसका संदेश अच्छा नहीं जाता है। लेकिन इसका हल एक-दूसरे को ऐसे मसले पर राजनीति न करने का सार्वजनिक उपदेश नहीं हो सकता। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को विशेष तौर पर चिंतित किया है। इस विशेष चुनौती से निपटने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को थोड़ा विस्तृत करने की जरूरत जायज तौर पर महसूस की गई हो, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इसके



बाद नोटिफिकेशन जारी करने से पहले संबंधित राज्यों से विचार-विमर्श करके उन्हें विश्वास में लेने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। यह नौबत क्यों आई कि फैसला लागू होने की घोषणा के बाद विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसे देश के संघात्मक ढांचे पर हमला बताने लगे? उनका पक्ष पहले सुन लिया जाता तो यह विरोध सार्वजनिक नहीं होता। तब यह भी संभव था कि उनकी चिंताएं दूर करने की कोई राह निकल आती। आखिर कानून व्यवस्था का सवाल राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक का दायरा किसी केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में देने से राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच टकराव की नौबत

आने की आशंका बढ़ जाती है। हो सकता है बीएसएफ की किसी कार्रवाई से कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो जाए। राज्य सरकारों के असंतोष या उनकी असहमति का सार्वजनिक रूप से जाहिर होना ऐसे संभावित टकराव की जमीन को मजबूत करता है। जाहिर है, इस प्रकरण में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था और जो थोड़ी सी सावधानी से टाला जा सकता था। फिर भी अभी बहुत देर नहीं हुई है। सार्वजनिक बयानबाजी से मामला सुलझने के बजाय और उलझता जाएगा। बेहतर होगा कि संबंधित राज्य सरकारों से अविलंब बातचीत शुरू करके उनकी शिकायतों पर गौर किया जाए। ऐसे संवेदनशील मसलों पर में कोई भी कदम तभी सफल होगा, जब वह पूरे तालमेल के साथ उठाया जाए।

जिज्ञासा

अशोक वोहरा। रात हुई। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का टिकाना न रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में बादाम के छिलके आड़ बनकर आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा भी नहीं सुना। वह पहले अपने घर गया और अपनी तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सब लोग कंजूस की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर हैरान में पड़ गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

राजनीति के खिलाड़ी

अशोक गहलोत पॉलिटिकल एम्ब्राइडरी में निष्णात हैं। वह सर्द शाम में ठिठुरते हुए लू लगने का बोध करवा सकते हैं और बदन झुलसाती लू के बारे में एहसास करवा सकते हैं कि शीतलहर कैसे कंपा रही है। वह हाईकमान की इच्छाओं का बहुत खयाल रखते हैं और प्रतिद्वंद्वियों को अपने से दायम दर्जे के नेताओं से तू तू मैं मैं में उलझाए रखते हैं। लेकिन इस बार पहला मौका था, जब पायलट के कारण तनाव में उनसे भाषा संबंधी मर्यादा टूटी और संयम जवाब दे गया। इन परिस्थितियों के बाद अब हुए मंत्रिमंडल विस्तार में दोनों खेमे प्रसन्न हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि जहां आजादी के बाद कांग्रेस के शुरुआती चार मंत्रिमंडलों में एक भी एससी-एसटी या महिला प्रतिनिधि नहीं था, वहीं इस बार पांच एसटी, चार एससी और तीन महिला मंत्री हैं।

यह पहला मौका है जब अगड़ी जातियों के नेताओं को मिलने वाले विभाग एसटी-एससी और महिलाओं को मिले हैं। उद्योग विभाग की कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक गुर्जर महिला और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदिवासी को जाएगा। लेकिन कांग्रेस अपने लिए बेहतर भविष्य तलाश करना चाहती है तो उसे अपने वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन और सहजता कायम करनी होगी। वह इन दोनों को आपस में लड़ते रहने देगी तो कहीं की नहीं रहेगी। कांग्रेस नेतृत्व के लिए जरूरी है कि वह अपने बेचौन और जल्दबाज युवाओं की धड़कनों को भी सुने और उन्हें संयमित रखे।

आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले तक पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री का कोई पोस्टर या बैनर तक नहीं था।

तकदीर का खेल

त्रिभुवन।।

राजस्थान में तीन साल से कांग्रेस सत्ता में है। इस बीच, पार्टी में जबर्दस्त खेमेबंदी दिखी है। एक खेमा दूसरे पर हावी होने के पैतरे आजमाता आया है। ताजा मंत्रिमंडल विस्तार को इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले तक पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री का कोई पोस्टर या बैनर तक नहीं था। यह तब है, जब संगठन का नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के ही पास है। खैर, पोस्टर-बैनर भले न लगा हो, लेकिन यहां कोई चेहरा है तो मुख्यमंत्री का ही है।

प्रदेश से बाहर पार्टी के युवा चेहरे सचिन पायलट का एक आकर्षण है। माना जा रहा है कि ताजा मंत्रिमंडल विस्तार उनकी वजह से ही हुआ है और यह उनकी कामयाबी है। यह सही भी है और नहीं भी। उनके विद्रोह से पहले के हिसाब से देखें तो उन्होंने काफी कुछ खोया है। लेकिन जिस तरह का कदम उन्होंने उठाया था, उसे देखते हुए वह खुद को संभालने में कामयाब रहे। इसे भी पायलट की उपलब्धि मान सकते हैं। तीन साल पहले उनके हाथों में दूध का कटोरा था। पार्टी को राज्य की 200 में से 100 सीटों पर जीत मिली थी। पायलट उस जीत के हीरो थे। उनके राजनीतिक कौशल का गुण गाने



वालों की कमी न थी। तब रेगिस्तानी सरजमीं पर जो खूबसूरत फूल अभी खिले नहीं थे, वे खुशबू का हिसाब करने लगे थे। इस प्रदेश में अंगेती और पछेती फसलें तो होती हैं, लेकिन जल्दबाजी में बोई गई फसलें लहलहा नहीं पातीं। सियासी सपनों की लहर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ताजा मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी काफी कुछ पायलट और गहलोत के अप्रिय रिश्तों से जुड़ी है। आप परिदृश्य देखेंगे तो एक समूह पायलट को इस विस्तार के बाद विजेता की तरह प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि गहलोत ही सब कुछ

हैं। इस सरकार के बनने से पहले हवाओं में यही था कि पायलट को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन गहलोत ने बाजी उलट दी। तो यह मंत्रिमंडल विस्तार भी बदन झुलसा देने वाली राजस्थानी लू की कहानी को अपने में समेटे है। यहां बहुत नेता आए हैं, जिन्हें रेत में सोना नजर आया, लेकिन उनकी जमीन इनकार के नशे में गुम हो गई। राजस्थान में आठ साल पहले पायलट को इस अभियान के तहत कमान सौंप कर भेजा गया था कि वह प्रदेश को एक नया नेतृत्व देंगे। उस समय हाईकमान और अशोक गहलोत के रिश्ते बिलकुल अच्छे नहीं थे। यह वह दौर था, जब अभी के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पार्टी नेताओं के लिए जलन की वजह बने हुए थे और गहलोत आंख की किरकिरी। इसकी वजह भी थी। उस समय उनकी सरकार बीजेपी के हाथों बुरी तरह से हारी। 200 सीटों में से कांग्रेस को मिली महज 21 सीटें। उस हार के बाद सचिन पायलट के दिन बदले। उनके सिर से सहसा हुमा पक्षी उड़कर निकल गया था यानी आगे चलकर उनके लिए सत्तासीन होने में कोई शकोशुबह न था। पुराने समय में बादशाहत का भी यही शगुन माना जाता था। इतना ही नहीं, यह परिदा उनके लश्कर के आगे आवाजें लगाता हुआ चल रहा था।

सूदिकु बचवाल-5353		****	
कठिना	कठिना	कठिना	कठिना
8	4		
1		9	
3	2	5	
	1	8	
5		4	
7	9		
6	3	2	
9		1	
	8	7	

अपना ब्लॉग

राजस्थान की सियासी इबारत

मोहन। नए मंत्रिमंडल विस्तार को समझने के लिए राजस्थान की सियासी इबारतों को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को देखना-समझना जरूरी है। सार इतना सा है कि एक नया चेहरा लगातार वाचल रहा और खुले में खेलता रहा। सियासत के पुराने खिलाड़ी चुप रहे और उनकी सियासत ने भी होंठ सिए रखे। इसका नतीजा यह निकला कि प्रदेश की सियासत का न पैरहन बदला और न लिबास। सरकार बदली, लेकिन मजूर वही रहा। आज हालात ऐसे हैं कि पायलट न उपमुख्यमंत्री हैं और न प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन उनके साथ उम्र है और अभी वह महज 44 साल के हैं। वह राहुल गांधी से सात साल छोटे हैं और अशोक गहलोत से 26 साल। यह बहुत बड़ी बात है। उम्र के इसी आंकड़े में उनके भविष्य की संभावनाएं छिपी और सिमटी हैं। पांच साल बीते। चुनाव हुए। नतीजे आए, लेकिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके लिए तब वह शहर जला हुआ सा मिला, जहां उन्हें सत्तासीन होना था।

